डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 मई, 2021, डिस्पेच दिनांक 16 मई, 2021

| वर्ष 64 | अंक 24 | भोपाल | 16 मई, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/– | आजीवन शुल्क 1500/– |

कोई भी गरीब बिना राशन के नहीं रहेगा : मुख्यमंत्री

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्थाएँ परफेक्ट हों ● मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निःशुल्क खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड संकटकाल में कोई भी गरीब बिना राशन के नहीं रहेगा। उन्होंने सहकारिता और खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नियम शिथिल कर इस संबंध में व्यवस्थाएँ की जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मुख्यमंत्री निवास से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह और सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद भदौरिया भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब व्यक्ति को खाद्यान्न प्राप्त करने में दिक्कत नहीं हो। पात्रता पर्ची, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज नहीं होने पर भी उनको अनाज का वितरण किया जाये। उन्होंने खाद्य एवं सहकारिता विभाग के मंत्रियों को इस संबंध में प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिये।

वितरण के समय भीड़ नहीं हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राशन वितरण के समय उचित मूल्य दुकान पर भीड़ नहीं लगे। कोरोना गाइड लाइन का प्रभावी पालन हो। इसकी प्रभावी व्यवस्था के साथ ही उसकी निगरानी भी की जाये। राशन वितरण के समय सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी को तैनात किया जाये।

हितग्राहियों को एस.एम.एस. से सूचित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हितग्राहियों को एस.एम.एस. द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की सूचना दी जाये। उन्होंने कहा कि कोविड संकट काल में निःशुल्क राशन वितरण के उठाव, परिवहन और वितरण चुनौती पूर्ण कार्य है। खाद्यान्न के परिवहन और वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाये। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता और कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। सहकारिता और खाद्य विभाग समन्वय और सामंजस्य के साथ कार्य करें।

पी.ओ.एस. मशीन से पावती

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के साथ ही हितग्राही को पी.ओ.एस. मशीन से पावती उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने कहा कि वितरण कार्य में गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

75 लाख किसानों के खाते में जमा हुए 15 सौ करोड़

उपार्जन और ऋण जमा करने की तिथियाँ बढ़ी ● कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में करें सहयोग ● मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के किसानों से की अपील

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में किसान मित्र सरकार है। किसान की फसल के एक–एक दाने का उपार्जन किया जाएगा। उपार्जन और ऋण वापसी की अंतिम तिथियाँ बढ़ा दी गई हैं। किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने किसानों और किसान संगठनों से अपील की है कि कोरोना के विरुद्ध चल रही लड़ाई में सहयोग करें। संक्रामक रोग होने के कारण सरकार अकेले दम पर नहीं जीत सकती। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज 75 लाख किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से जमा कर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किसानों को मुख्यमंत्री निवास से संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल भी प्रदेश के किसानों सहित वेब लिंक से जुड़े।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि छोटे किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही उपज का उपयोग कर लेते हैं। उनको खरीदी योजनाओं के लाभ नहीं मिल पाते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार रुपए देने की व्यवस्था गत वर्ष से की गयी है। इस योजना में आज 75 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अंतरित किये गये।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि वरदान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 78 लाख किसान हैं, जिनमें से केवल 24 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा मिल पाता है। प्रधानमंत्री की योजना से आधे एकड़ के किसानों को भी वर्ष में 6 हजार रुपए केन्द्र सरकार की ओर से मिलते हैं। योजना में 77 लाख किसानों को लगभग 8 हजार 465 करोड़ रुपए अब तक मिले हैं।

गेहूँ की 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हुई खरीदी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूँ और एक लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चने की खरीदी हुई है। मसूर भी खरीदी जा रही है। इंदौर संभाग के लिए खरीदी की तिथि 5 मई से बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। अन्य संभागो में 25 मई तक खरीदी होगी।

ऋण चुकाने की तिथि अब 31 मई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के खाते में समय पर राशि अंतरित हो। कठिनाईयों के बावजूद निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शून्य प्रतिशत ब्याज पर प्राप्त ऋण चुकाने की अंतिम तिथि को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस निर्णय से सरकार द्वारा बैंको को 31 करोड़ रुपए ब्याज के रुप में देने पड़ेंगे।

सावधानी के साथ उपार्जन केन्द्र जायें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से अनुरोध किया कि उपार्जन केन्द्र पर केवल जरुरी हो, वही जायें। व्यक्ति पूरी सावधानी के साथ मास्क लगाकर जाए। सामाजिक दूरी के साथ कार्य करें। निरंतर हाथों को सेनेटाइज करते रहें।

खरीदी कार्य से जुड़े व्यक्तियों की सराहना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहकारिता, खाद्य, मंडी के मजदूरों, हम्मालों एवं अन्य विभागों के अधिकारी–कर्मचारियों द्वारा अपने जीवन को संकट में डाल कर खरीदी कार्य जारी रखने के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की सरकार किसान मित्र सरकार है। खरीफ फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत का वितरण सरकार द्वारा किया गया है। फसल बीमा की राशि भी किसानों के खातों में शीघ्र जमा होगी। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसान परेशान नहीं हो।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

गरीब परिवार को 3 माह में 25 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रति व्यक्ति निःशुल्क मिलेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा गेहूँ उपार्जन कार्य की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब परिवारों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दिये जाने वाले खाद्यान्न के साथ ही केन्द्र सरकार से प्राप्त 10 किलो खाद्यान्न का वितरण भी किया जाए। इस तरह परिवार के प्रत्येक सदस्य के मान से 25 किलोग्राम अनाज तीन माह में गरीबों को निरूशुल्क प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले इसके लिए व्यापक स्तर पर जन–जागृति के कार्य किए जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस से गेहूँ उपार्जन कार्य की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संक्रमण चुनौती के काल में खाद्य विभाग और सहकारिता क्षेत्र के कर्मचारियों अधिकारियों के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि जो हितग्राही अप्रैल–मई माह का अनाज ले गए हैं उनको जून माह में अतिरिक्त आंवटन की पूर्ति की जाए। श्री चौहान ने गेहूँ उपार्जन कार्य की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए परिवहन कार्य में और अधिक गति लाने के प्रयास करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उपार्जन एवं राशन वितरण व्यवस्थाओं में संक्रमण से बचाव की सावधानियों का पूरी गम्भीरता से पालन होना चाहिए। राशन वितरण में बॉयोमेट्रेक्सि व्यवस्था से छूट दी जाए। मास्क पहनने और सेनेटाइजेशन की व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन हो।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया गया कि खरीदी की अवधि बढ़ाने और पोर्टल को शनिवार को खुला रखने के कार्य किए गए हैं। जिन खरीदी केन्द्रों में 5 मई तक खरीदी होनी थी, वहां अब 15 मई तक खरीदी का कार्य किया जाएगा। इसी तरह 15 मई तक खरीदी केन्द्रों में 25 मई तक खरीदी होगी। इसी तरह खरीदी केन्द्रों की क्षमता के अनुसार एस.एम.एस भेजे जा रहे हैं ताकि केन्द्रों पर भीड़ एकत्र नहीं हो। उनको बताया गया कि प्रदेश में खरीदी की मात्रा के अनुसार बारदाने उपलब्ध हैं। प्रदेश में कुल सत्यापित 24 लाख 65 हजार सत्यापित किसानों में से 16 लाख 5 हजार किसानों को एस.एम.एस भेजे गए हैं।

इनमें से 7 लाख 32 हजार किसानों से 10 हजार 596 करोड़ रूपए का 53 लाख 69 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न की खरीदी हो चुकी है। किसानों को 6 हजार 683 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। भुगतान 5 दिवस की अवधि में किया जा रहा है। प्रदेश में 4 हजार 588 खरीदी केन्द्रों द्वारा खरीदी का कार्य किया जा रहा है। सभी 94 सेक्टरों में उपार्जन ऐंजेंसी द्वारा परिवहन कर्ता नियुक्त हैं।

गरीबों का हित सरकार की पहली प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 379 करोड़ रूपये संबल हितग्राहियों के खातों में किए अंतरित ● 16 हजार 844 हितग्राही लाभान्वित

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों का हित करना राज्य शासन की प्राथमिकता में है। गरीब मजदूर वर्ग को संकट के समय संबल देने के लिये ही संबल योजना बनाई गई है। योजना में आज प्रदेश के 16 हजार 844 हितग्राहियों के खाते में 379 करोड़ रुपये अंतरित किये गये हैं। कोरोना काल के संकट में यह सहायता राशि गरीब परिवारों के लिये काफी उपयोगी साबित होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंगलवार को असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिक परिवारों को मुख्यमंत्री जन–कल्याण संबल योजना में सहायता राशि वितरण कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में श्रम मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह भी वर्चुअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राहियों से संवाद करते हुए कहा कि संकट के कठिन समय में संबल योजना के 16 हजार 844 हितग्राहियों को की गई आर्थिक मदद के साथ तीन माह का निःशुल्क राशन भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। कोरोना की जंग में प्रदेशवासियों का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने हितग्राहियों का आव्हान किया कि वे कोरोना के प्रति सावधानियाँ बरतें और स्वयं के साथ दूसरों को भी बचायें।

संबल योजना गरीबों की ताकत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना गरीबों की ताकत है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन–कल्याण संबल योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिक परिवारो के सदस्यों की मृत्यु, अपंगता, आंशिक अपंगता की स्थिति में उन्हें अथवा उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना की शुरूआत से अब तक विगत तीन वर्षो में प्रदेश के 2 लाख 44 हजार 844 हितग्राहियों अथवा उनके परिजनों के खातों में 2 हजार 286 करोड़ की राशि अंतरित की गई है।

संबल योजना के अंतर्गत श्रमिकों की दुघर्टना मृत्यु पर 4 लाख रूपये की राशि उनके आश्रितों को दी जाती है। इसी प्रकार सामान्य मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में 2–2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि मुख्यमंत्री जन–कल्याण संबल योजना में दी जाती है। श्रमिक के आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में उसे एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता एवं अंत्येष्ठि सहायता के रूप में 5 हजार रूपये दिये जाने का प्रावधान भी योजना में है।

सर्वाधिक 3398 हितग्राही जबलपुर संभाग से

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंगल क्लिक के द्वारा भोपाल संभाग में 1645 हितग्राहियों के खातों में 3 हजार 782 लाख रूपये, चंबल संभाग में 658 हितग्राहियों को 1422 लाख रूपये, ग्वालियर संभाग में 1058 हितग्राहियों को 2404 लाख एवं इंदौर संभाग में 2 हजार 587 हितग्राहियों को 5716 लाख रूपये उनके खातों में हस्तांरित किये। जबलपुर संभाग में सर्वाधिक 3 हजार 398 हितग्राहियों को 7526 लाख रूपये,होशंगाबाद में 893 हितग्राहियों को 2062 लाख रूपये, रीवा में 1316 हितग्राहियों को 3020 लाख रूपये, सागर में 2326 हितग्राहियों को 5240 लाख रूपये ,शहडोल में 672 हितग्राहियों को 1490 लाख रूपये और उज्जैन में 2291 हितग्राहियों को 5172 लाख रूपये उनके खातों में आज हस्तांरित किये गये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब परिवारों को तीन माह का राशन एकमुश्त प्रदान किया जा रहा हैं। जिन्होंने अप्रैल माह के राशन का भुगतान कर दिया है। उन्हें जुलाई माह का राशन निःशुल्क दिया जायेगा। चूँकि यह लड़ाई घर में बैठकर ही लड़ी जायेगी तभी जीती जा सकती है। आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं, राशन आपको निःशुल्क घर पर ही उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि आप लोग बीमारी को छुपाएँ नहीं। प्रारंभिक रूप से सर्दी खाँसी का पता लगते ही डॉक्टर्स को बताएँ आपको निःशुल्क मेडिकल किट दी जायेगी। आप घर पर रहकर ही ठीक हो सकते हैं।

बिजली कार्मिकों को उपचार के लिए मिलेगा कोविड–19 चिकित्सा अग्रिम

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कोविड–19 पीड़ित बिजली कंपनी के नियमित कार्मिकों को विषम एवं गंभीर परिस्थितियों में चिकित्सा उपचार की सुविधा मुहैया कराने के लिए ''कोविड–19 चिकित्सा अग्रिम तत्काल सहायता योजना'' स्वीकृत की है। कंपनी के नियमित कार्मिकों के लिए कोविड–19 से पीड़ित होने पर उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए 3 लाख रूपये का अग्रिम तत्काल स्वीकृत किया जाएगा। यह चिकित्सा अग्रिम संबंधित कार्मिक की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, चिकित्सक की उपचार पर्ची एवं अस्पताल में भर्ती होने की सलाह संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जाएगा। इसके लिए मैदानी स्तर पर क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी मुख्यालय में मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) को स्वीकृति के अधिकार दिए गए हैं। चिकित्सा अग्रिम प्राप्त करने वाले संबंधित कार्मिक को आदेश जारी होने की दिनांक से छः माह के भीतर चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना होगा। यह योजना 24 अप्रैल से आगामी तीन माह के लिए लागू रहेगी।

कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर संघर्ष जारी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने बीना पहुँचकर ग्राम चक्क में बन रहे अस्थाई अस्पताल की प्रगति देखी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर संघर्ष जारी है। संक्रमित भाई–बहनों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। राज्य शासन की दोहरी रणनीति है, जिसमें एक ओर संक्रमण को बढ़ने से रोका जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज भारत–ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, बीना के समीप बनाए जा रहे अस्थाई अस्पताल का निरीक्षण किया।

उल्लेखनीय है कि, कोरोना संक्रमितों के उचित उपचार तथा संक्रमित व्यक्तियों को पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था के उद्देश्य से बीओआरएल (भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड) के पास करीब पाँच सौ मीटर की दूरी पर ग्राम चक्क (आगासोद) में एक हजार पलंग की क्षमता वाला एक अस्थाई अस्पताल बनाया जा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इस दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ किया जाए।

इसकी समीक्षा करने मुख्यमंत्री श्री चौहान मंगलवार दोपहर स्वयं बीना पहुँचे जहाँ उन्होंने अस्पताल स्थल पर संपूर्ण कार्य–योजना को समझा तथा प्रोजेक्ट, ले–आउट और अन्य तैयारियों की जानकारी ली।

कोविड संक्रमितों के इलाज हेतु ग्राम चक्क में बन रहे इस अस्पताल में अन्य सुविधाओं के साथ मुख्य रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। बीना रिफाइनरी के ऑक्सीजन प्लांट से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित कर रिफाइनरी से अस्थाई अस्पताल तक मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बनी रहेगी।

हवा, पानी की उत्तम व्यवस्था और आग से बचाव का हो विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बीओआरएल में समीक्षा बैठक भी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि अस्पताल निर्माण में हवा, पानी की उत्तम व्यवस्था हो और आग से बचाव का विशेष ध्यान रखा जाये। रिफाइनरी के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि बीओआरएल के वॉटर सोर्स से करीब 4 हजार मीटर की पाईप लाईन द्वारा हॉस्पिटल डोम तक पानी पहुँचाया जायेगा। बीओआरएल में 12 लाख लीटर पानी की क्षमता के डववेल हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति मरीज दिया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि अस्थाई अस्पताल के लिए डॉक्टर, पेरामेडिकल स्टॉफ, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आदि बाहर से आएँगे। अतः उनके रुकने का अच्छा इंतजाम किया जाए और तत्काल 100 बिस्तरों का अस्पताल तैयार कर उसका प्रारंभिक परीक्षण कराया जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा, चूँकि मरीज ज्यादा चल नहीं सकता, अतः उसकी सुविधा के लिये शौचालय ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अस्पताल के पास में ही लैब होना चाहिए। उन्होंने बिजली लाइन के लिए सब स्टेशन तत्काल तैयार करने और निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

डीआरडीओ और अहमदाबाद की टीम से मिल रहा आवश्यक सहयोग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि, अस्थाई अस्पताल के सेटअप तथा बीओआरएल से अस्थाई अस्पताल तक ऑक्सीजन सप्लाई के लिए डीआरडीओ से आवश्यक तकनीकी सहायता मिल रही है। ऑक्सीजन पाइप–लाइन के लिये अहमदाबाद की टीम का भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि, ऑक्सीजन पाईप लाइन अस्पताल परिसर के डोम तक आयेगी। अतः कम्प्रेशर आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था रखी जाये। बैठक में जानकारी दी गई कि बीओआरएल से अस्पताल के डोम तक कॉपर पाईप के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई कर मरीजों तक पहुँचाई जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि, अस्पताल परिसर में एक ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) भी बनाई जाए, जिससे मरीज परामर्श ले सकें और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भर्ती किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल से सागर, विदिशा, रायसेन और बुंदेलखंड के मरीज लाभान्वित होंगे।

कमजोर वर्ग एवं प्रवासी मजदूरों के प्रत्येक परिवार को मिले निःशुल्क खाद्यान्न : सहकारिता मंत्री

भोपाल। कमजोर एवं प्रवासी मजदूरों के प्रत्येक परिवार को पात्रता पर्ची न होने पर स्व सत्यापित प्रमाण–पत्र के आधार पर निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाये। यह बात सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने खाद्यान्न वितरण की राज्य स्तरीय वर्चुअल समीक्षा मीटिंग में कही। बैठक में खाद्य मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह भी उपस्थित थे।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान की घोषणा के अनुसार तीन माह का तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का दो माह के निःशुल्क खाद्यान्न सहित प्रत्येक पात्र परिवार को 5 माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक गरीब परिवार को निःशुल्क खाद्यान्न मिले, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड–19 महामारी में लॉकडाउन के कारण अधिकतर लोगों का रोजगार बंद है। ऐसे नाजुक हालात में कोई भी नागरिक खाद्यान्न की कमी के कारण भूखा न रहे, इसलिए सहकारी समितियाँ पहली प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण ईमानदारी से खाद्यान्न वितरण का कार्य करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए

कोरोना गाइड–लाइन का सख्ती से पालन किया जाये। उपभोक्ताओं को उचित दूरी पर रखकर ही खाद्यान्न वितरण किया जाये। राशन वितरण दुकानों को पूरे माह खोला जाये, ताकि ज़्यादा भीड़ जमा न हो।

वृद्ध लोगों के घर पहुँचायें निःशुल्क खाद्यान्न

डॉ . भदौरिया ने निर्देश दिए की वृद्ध लोगों के घर तक निःशुल्क खाद्यान्न पहुँचाने की व्यवस्था की जाये। मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों की कोरोना काल में काम करने में आ रही परेशानियों को दूर किया जायेगा। साथ ही जायज माँगों को शीघ्र–अतिशीघ्र पूरा किया जायेगा। उन्होंने खाद्यान्न वितरण का कार्य अभियान के रूप में करने के निर्देश दिये।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने लक्ष्य से कम खाद्यान्न वितरण पर सागर, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना के अधिकारियों को फटकार लगाई तथा निर्देश दिये कि मई माह के अंत तक शत–प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करें। खाद्य मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह ने कहा कि माँग के अनुसार निर्धारित समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जा चुकी है। सभी केंद्रों पर कोरोना गाइड–लाइन का पूर्ण पालन करते हुए वितरण किया जाये। प्रमुख सचिव, खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की 25 पात्र श्रेणियों के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को निःशुल्क खाद्यान्न का लाभ दिया जाये। पात्रता पर्ची, आधार कार्ड आदि प्रमाण–पत्र न होने पर स्व–सत्यापित प्रमाण–पत्र के आधार पर पात्र हितग्राही को खाद्यान्न वितरण किया जाये। स्थानीय निकायों से ऐसे परिवारों की अस्थाई पात्रता पर्ची जारी कराई जाये। ऐसे सभी पात्र परिवारों की एंट्री विभाग द्वारा बनाये गए मॉड्यूल में करने के निर्देश दिये गये।

शहीद कोरोना योद्धा के परिजन को मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति और 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि

भोपाल। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पुलिस के जवानों और परिजनों का अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिये वैक्सीनेशन शिविर लगाये जायें। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस जंग में शहीद होने वाले कोरोना योद्धाओं के परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी। परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त पुलिस के सेंट्रल वेलफेयर फण्ड से एक लाख रुपये की सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जायेगी। डॉ. मिश्रा पुलिस कंट्रोल रूम इंदौर में कोविड–19 के संबंध में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे।

डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि फील्ड में कार्य कर रहे जवानों के कोरोना संक्रमित होने पर अस्पतालों से समन्वय कर उन्हें उपचार के लिये भर्ती कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में कोरोना से जंग को जीतना है। सभी को अपना मनोबल ऊँचा रखना है और फील्ड में कार्य कर रहे जवानों की निरंतर हौसला अफजाई करते रहना है। डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो उन्हें तत्काल अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि आवश्यक प्रबंध कर समस्याओं का निराकरण किया जा सके। बैठक में बताया गया कि इंदौर में पुलिस के 111 जवान कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें 106 घर पर आइसोलेशन में हैं। शेष 5 कोरोना पॉजिटिव जवान अस्पताल में उपचाररत हैं।

बैठक में जल–संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, क्षेत्रीय सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायकगण और पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने शुरू किया पुलिस कोविड केयर सेंटर

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में पुलिस डीआरपी लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए 50 बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर की शुरूआत की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 742 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वर्तमान में पुलिसकर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है, ताकि जवानों को त्वरित बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सके। डॉ. मिश्रा ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में पुलिसकर्मियों द्वारा अथक परिश्रम किया जाकर अपना कर्त्तव्य निर्वहन किया जा रहा है। डॉ. मिश्रा ने कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स और मेडिकल वर्कर्स से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर जल–संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, क्षेत्रीय सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक द्वय श्री रमेश मेंदोला और श्री महेन्द्र हार्डिया भी मौजूद थे।

1.11 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को एक मुश्त मिलेगा 3 माह का राशन : खाद्य मंत्री श्री सिंह

भोपाल। खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि राज्य शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित एक करोड़ 11 लाख 32 हजार पात्र परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 का एक मुश्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये पात्र हितग्राहियों को एक मुश्त राशन दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इसके अन्तर्गत हितग्राहियों को निरूशुल्क राशन वितरित किया जायेगा। इस पर होने वाला व्यय राज्य शासन स्वयं वहन करेगा। जिन हितग्राहियों द्वारा अप्रैल अथवा मई माह का एक रूपये प्रति किलो की दर से भुगतान किया जाकर राशन प्राप्त किया

गया है, उन्हें जुलाई एवं अगस्त माह का खाद्यान्न निःशुल्क दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सम्मिलित पात्र हितग्राही अतिरिक्त रूप से 5 किलोग्राम प्रतिमाह प्रति–व्यक्ति की दर से मई एवं जून में खाद्यान्न निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। यह खाद्यान्न राज्य शासन द्वारा प्रतिमाह दिये जाने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा।

वन नेशन–वन राशन कार्ड

खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि वन नेशन–वन राशन कार्ड के तहत प्रवासी मजदूर जो पात्रता श्रेणी के अनुसार राशन कार्ड धारी हैं, को पोर्टेबिलिटि के माध्यम से प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार के ''मेरा राशन'' मोबाइल एप पर ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को पंजीयन करने की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे उन्हें सुविधाजनक तरीके से खाद्यान्न वितरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी पात्रता धारी प्रवासी मजदूर अपने स्थानीय निकाय में जाकर पंजीयन करायें ताकि उन्हें पोर्टेबिलिटि के अन्तर्गत राशन सामग्री प्राप्त हो सके।

कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गांव के दरवाजे करें बंद : मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के ग्रामवासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आप लोग कोरोना को अपने गाँव की सरहद में प्रवेश नहीं करने दें। अपने गाँव को बंद रखें। जब जरूरत हो, तभी गाँव के बाहर निकलें। उपार्जन के लिए सिर्फ वे ही बाहर जायें, जिनके नाम एसएमएस भेजा गया है। जब भी बाहर निकलें तो कोरोना गाइड–लाइन का पूरी तरह से पालन करें। स्वतः स्फूर्त कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू।

गेंहूँ उपार्जन में कोई बाधा नहीं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामवासियों से कहा कि आप लोग निश्चित रहें। आपकी उपज का एक–एक दाना खरीदा जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गेहूँ उपार्जन में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह हौंसले का ही परिणाम है कि अभी तक 61 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ का उपार्जन कर लिया गया है। इसी के साथ चने एवं मसूर का उपार्जन भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले साल कोरोना के चरम में भी हमने 1.29 लाख मीट्रिक

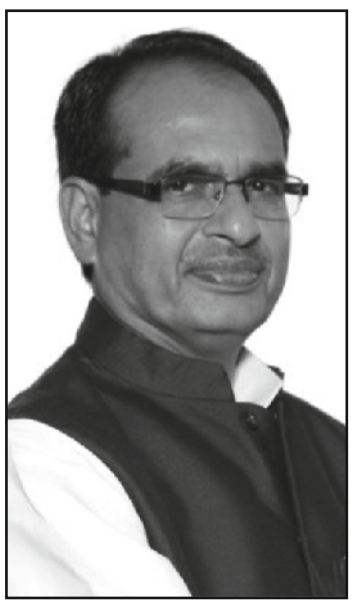

टन गेहूँ का बम्पर उपार्जन किया था। कोरोना काल में सभी किसानों का गेहूँ खरीदा जा सके, इसके लिये इंदौर एवं उज्जैन में उपार्जन की अंतिम तिथि 5 मई से बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। शेष संभागों में 25 मई तक खरीदी की जायेगी।

कोरोना साध्य है, असाध्य नहीं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना साध्य है, असाध्य नहीं। इसका इलाज हो सकता है और हो रहा है। इससे घबरायें नहीं सतर्कता अवश्य रखें।

उन्होंने कहा कि सामान्य सर्दी–जुकाम–बुखार आने पर लापरवाही न करें। तुरंत जाँच करवायें। किल कोरोना अभियान–2 के तहत हमारी टीम घर–घर पहुँच रही है। पॉजिटिव आने पर होम आइसोलेशन में रहें। घर में संभव हो तो एक पृथक कमरे में आराम कर उपचार करें। यदि घर में संभव न हो, तो गाँव के पंचायत भवन, धर्मशाला, आदि में क्वारेंटाइन सेंटर बनाकर आइसोलेटेड हो जायें। भोजन दवा की व्यवस्था सरकार करवायेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकासखंड में कोविड कोरोना सेंटर खोले जा रहे हैं। वहाँ डाक्टर्स उपलब्ध हैं। उन्हें दिखाकर उपचार लिया जा सकता है। हॉस्पिटल को अंतिम पड़ाव पर रखें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामवासियों और किसानों से अपील की कि विवाह हमारी परंपरा है और संस्कार का महत्वपूर्ण भाग है। परंतु वर्तमान कोरोना संक्रमण के कारण विवाह समारोह को 15 मई तक स्थगित रखें, क्योंकि ऐसे समारोह में कोरोना पूरे परिवार को सामूहिक रूप से प्रभावित कर सकता है। यदि बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो अधिक से अधिक 10 लोग ही शादी में शामिल हों।

कोरोना से मृत्यु पर मंडी कर्मचारियों के परिजनों को मिलेंगे 25 लाख रु. : मंत्री श्री पटेल

मंडी के 31 कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगी सहायता राशि इलाज के लिये मिलेगी अग्रिम राशि

भोपाल : किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि कोरोना संक्रमण काल में मंडी बोर्ड के 31 कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण करते हुए महामारी के काल के गाल में समा गये। उन्होंने मृतक कर्मचारियों को श्रद्धासुमन अर्पित किये हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 25–25 लाख रूपये की सहायता दी जायेगी, साथ ही मंडी बोर्ड एवं समितियों के कर्मचारियों के परिजनों को इलाज के लिये अग्रिम राशि भी दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

श्री पटेल ने कहा कि समस्त मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 25–25 लाख रूपये की सहायता राशि मंडी बोर्ड की ओर से प्रदान की जायेगी। सहायता राशि प्रदान करने में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जायेगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के परिजनों को भी 25 लाख रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। श्री पटेल ने कहा कि मंडी बोर्ड और समिति सदस्यों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उपार्जन का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि मृतक कर्मचारियों के परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश एम.डी. मंडी बोर्ड सुश्री प्रियंका दास को दिये गये हैं।

अस्पताल में निःशुल्क औषधि युक्त चाय वितरण केंद्र शुरू

भोपाल। जिला चिकित्सालय सीहोर में कोविड–19 मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित दुर्गावती संकुल स्तरीय स्व–सहायता समूह ने निःशुल्क चाय एवं गर्म पानी वितरण के लिए स्टॉल लगाया है। इस स्टॉल से अस्पताल में भर्ती कॉविड 19 के मरीजों एवं उनके परिजनों को निःशुल्क चाय एवं गर्म पानी वितरित किया जाएगा। मरीजों को जो चाय दी जाएगी वह आयुर्वेदिक औषधि युक्त होगी, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होगी।

दुर्गावती आजीविका संकुल स्तरीय संघ सीहोर की अध्यक्ष श्रीमती धापू बाई ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर इस स्टॉल की शुरूआत की है। यह सुविधा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी। यहाँ सेवा करने वाले कर्मचारी के लिये कोविड–19 से बचाने के लिये समुचित प्रबंध किये हैं। इस कार्य में लगने वाली समस्त राशि जन–सहयोग से ही एकत्र की जायेगी।

गाँव–गाँव में जागरूकता की अलख जगा रहे कोरोना वॉलेंटियर्स

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ''मैं भी कोरोना वॉलेंटियर'' अभियान के तहत सीहोर जिले में म.प्र. जन अभियान परिषद के कोरोना वॉलेंटियर्स गाँव–गाँव में जन–जागरूकता की अलख जगा रहे हैं। कोरोना वॉलेंटियर्स गाँवों में दीवार लेखन, पोस्टर सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन करने तथा घरों में ही रहने की समझाईश दे रहे हैं। साथ ही मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और समय–समय पर साबुन से हाथ धोने की भी समझाईश दे रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

कोरोना वॉलेंटियर्स ग्रामीणों के मन में व्याप्त वैक्सीन से जुड़ी भ्रांतियों को सहज और सरल रूप से संवाद कर दूर कर रहे हैं और कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर उन्हें स्वास्थ्य केन्द्रों तक ले जाकर वैक्सीन लगवाने में भी मदद कर रहे हैं। कोरोना वॉलेंटियर्स प्रचार–प्रसार की विभिन्न गतिविधियों के साथ ग्रामीणों तक संदेश पहुँचा रहे हैं कि यदि मास्क नहीं पहनोगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करोगे, तो कोरोना हो सकता है। इसलिए जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगायें। वालेंटियर्स द्वारा मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को निःशुल्क मास्क का वितरण करते हुए अपील की जा रही है कि कोरोना के खिलाफ मास्क हमारा सुरक्षा कवच है, इसे जरूर पहनें।

गर्व है महिला कोरोना योद्धा पर

नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू वार्ड में पदस्थ स्टाफ नर्स दीपमाला सरकार ने कोरोना के लक्षण दिखने पर जब अपना कोविड टेस्ट कराया, तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चूँकि दीपमाला का परिवार छिन्दवाड़ा में रहता है और यहाँ किराये के मकान में रहती हैं। लेकिन उन्होंने बगैर घबराए हिम्मत से काम लिया और घर में क्वारेंटाइन हो गईं। उन्होंने 14 दिन तक कोरोना से डटकर मुकाबला किया और धैर्य बनाये रखा। जल्द ही स्वस्थ होने के बाद उन्होंने फिर से ड्यूटी ज्वाइन की और मरीजों की सेवा में जुट गईं। ऐसे कोरोना योद्धा पर सभी को गर्व है।

हितग्राहियों के सत्यापन एवं अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित

जिला कलेक्टर्स को जारी किये निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के चलते गरीब परिवारों को पात्रतानुसार खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में पात्रता पर्ची विहीन और छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण के लिये हितग्राहियों के सत्यापन एवं अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अस्थाई पात्रता पर्ची के लिये निर्धारित की गई प्रक्रिया सभी कलेक्टर्स को भेजते हुए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

पात्रता श्रेणी

हितग्राहियों के सत्यापन एवं पात्रता पर्ची जारी करने और छूटे हुए हितग्राहियों के सत्यापन में एनएफएसए, 2013 अंतर्गत निर्धारित 24 श्रेणियों के पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने पर हितग्राही द्वारा संबंधित श्रेणी में होने का आवेदन सह–घोषणा–पत्र स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करना होगा। स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन सह–घोषणा–पत्र के पर्याप्त प्रिन्ट/छायाप्रति पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे। स्थानीय निकाय में प्राप्त आवेदन सह–घोषणा–पत्रों की पंजी संधारित की जायेगी। परिवार की समग्र आईडी होना अनिवार्य है, यदि परिवार की समग्र आईडी जारी नहीं हुई है, तो तत्समय ही स्थानीय निकाय द्वारा समग्र परिवार आईडी निर्मित की जायेगी। नवीन आवेदक को परिवार के सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने की अनिवार्यता नहीं है। परिवार के जिन सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध हों, उनकी प्रविष्टि पोर्टल पर की जायेगी।

सत्यापन

स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन का निर्धारित बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाएगा। आवेदक संबंधित ग्राम/वार्ड का निवासी है। परिवार एनएफएसए की पात्रता श्रेणी के अंतर्गत अर्हता रखता है। आवेदन में परिवार के एक सदस्य का सही मोबाईल नंबर उपलब्ध कराया गया है। आवेदक परिवार या उसके किसी भी सदस्य का नाम पूर्व से जारी पात्रता पर्ची में शामिल नहीं है। समग्र परिवार

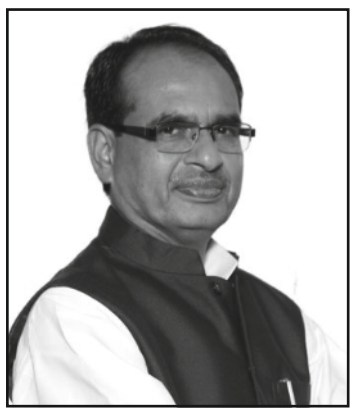

आईडी सही अंकित की गई है एवं आवेदन तथा समग्र आईडी डाटा में उल्लेखित परिवार के वितरण का मिलान हो रहा है। सत्यापन की कार्यवाही अधिकतम दो कार्य दिवस में पूर्ण की जायेगी। वार्ड प्रभारी/ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उक्तानुसार आवेदन का परीक्षण उपरांत जानकारी सही पाये जाने पर राशन मित्र पोर्टल पर आपदा खाद्यान्न राहत मॉड्यूल में आवेदक की जानकारी प्रविष्ट की जायेगी तथा हितग्राही को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने के लिये आवेदन जनपद/नगरीय निकाय को अग्रेषित किया जावेगा। जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय से अग्रेषित आवेदनों का परीक्षण उपरांत स्वीकृत/अस्वीकृत करने की कार्यवाही राशन मित्र पोर्टल पर की जायेगी। आवेदन को अस्वीकृत करने की दशा में अस्वीकृत करने का कारण अंकित करना होगा। वास्तविक पात्र हितग्राहियों को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने का उत्तरदायित्व स्थानीय निकाय/सत्यापनकर्ता अधिकारी का होगा।

अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करना

स्थानीय निकाय द्वारा आपदा खाद्यान्न राहत श्रेणी अंतर्गत परिवार के सत्यापन उपरांत एनआईसी द्वारा साप्ताहिक रूप से अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जायेगी। जारी पात्रता पर्ची में अस्थाई पात्रता पर्ची का उल्लेख किया जायेगा, जो कि आगामी तीन माह तक वैध होगी। तीन माह की समयावधि में हितग्राही द्वारा पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने पर स्थाई पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी। अस्थाई पात्रता पर्ची राशन मित्र पोर्टल पर उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका प्रिन्ट स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही को उपलब्ध कराया जायेगा। अस्थाई पात्रता पर्ची जारी होने की सूचना हितग्राही के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी।

खाद्यान्न का आवंटन

निर्धारित की गई प्रक्रिया के तहत जोड़े गए नवीन परिवारों के लिये एन.एफ.एस.ए अंतर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न गेहूँ एवं चावल का आवंटन जारी किया जायेगा। उचित मूल्य दुकान पर आवंटित खाद्यान्न के प्रदाय की प्रत्याशा में दुकान पर उपलब्ध स्टाक में से हितग्राही को खाद्यान्न का वितरण कराया जायेगा। योजना अंतर्गत खाद्यान्न प्रदाय की प्रतीक्षा किये बगैर हितग्राही को खाद्यान्न वितरण कराया जायेगा।

वितरण

अस्थाई रूप से जोड़े गए नवीन हितग्राहियों को पीओएस मशीन से खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। इसके लिए आपदा खाद्यान्न राहत श्रेणी अंतर्गत पृथक से पीओएस मशीन पर प्रदर्शित होंगे। पात्र हितग्राही को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी होने के माह से खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता होगी। परिवार को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न वितरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पीएमजीकेएवाय अंतर्गत माह मई एवं जून, 2021 का कुल 10 किलोग्राम खाद्यान्न भी निःशुल्क वितरण किया जायेगा। हितग्राही को खाद्यान्न वितरण करते समय पीओएस मशीन से जारी पावती आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए।

प्रचार–प्रसार एवं निगरानी

नवीन परिवारों को जोड़ने एवं उनको खाद्यान्न वितरण के संबंध में स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार कराने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही जन–प्रतिनिधियों को भी इस संबंध में अवगत कराया जाये। प्राप्त आवेदनों के सत्यापन, पोर्टल पर प्रविष्टि, अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने एवं खाद्यान्न वितरण की प्रतिदिन पंचायतवार/ निकाय वार मॉनिटरिंग की जाये। हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करने एवं राशन वितरण में कोविड–19 के बचाव के लिये निर्धारित प्रोटोकॉल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। श्री किदवई ने कहा कि अस्थाई रूप से जोड़े गए परिवारों द्वारा निर्धारित अवधि में पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर उनको जारी अस्थाई पात्रता पर्ची आमान्य कर दी जायेगी।

सर्विलांस टीम द्वारा डोर-टू-डोर कोरोना सर्वे एवं औषधि किट का वितरण

कोरोना मुक्त ग्राम अभियान

भोपाल। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए होशंगाबाद जिले में ''कोरोना मुक्त ग्राम'' अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में जिले की 421 ग्राम पंचायतों में एएनएम, आशा एवं आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सर्विलांस टीम द्वारा द्वारा घर–घर जाकर कोरोना सर्वे किया जा रहा हैं। साथ ही आमजनो /होम आइसोलेटेड मरीजों को औषधि किट का वितरण और कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी एवं सतर्कता बरतने की सलाह भी दी जा रही हैं। कलेक्टर श्री धनंजय सिंह ने बताया कि कोरोना नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आव्हान पर जिले की 421 ग्राम पंचायतों के 973 ग्रामों में ग्रामीणों द्वारा स्व–प्रेरणा से जनता कर्फ्यू के पालन का संकल्प लिया है। ग्रामीणों द्वारा ग्राम के प्रवेश मार्गों की सीमाओं को सील कर रोका–टोकी एवं पहरेदारी की जा रहीं हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए संकल्प–पत्र भी भरा गया है। पंचायत के सफाई कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों, सार्वजनिक भवनों एवं विभिन्न वार्डो में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है।

अंतर्जातीय विवाह के प्रस्ताव भेजने के लिये जिला कलेक्टर अधिकृत

भोपाल। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सामाजिक एकीकरण के लिये डॉ. अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रो इंटरकास्ट मैरिज प्रारंभ की गई है। डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के प्रावधान अनुसार डॉ. अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रो इंटरकास्ट मैरिज के प्रस्ताव भारत सरकार को सीधे अग्रेषित करने के लिये जिला कलेक्टर अधिकृत हैं।

अनुसूचित जाति के युवक या युवती द्वारा सवर्ण युवक या युवती से विवाह करने पर योजना में ढाई लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह योजना सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू होकर मध्यप्रदेश में भी क्रियान्वित की जा रही है। योजना में 500 दम्पतियों को प्रोत्साहित किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी का अवलोकन भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के पोर्टल ambedkarfoundation.nic.in पर किया जा सकता है।

महिला–बाल विकास विभाग की पहल

कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण–पोषण की जिम्मेदारी का लिया निर्णय

भोपाल। महिला–बाल विकास विभाग द्वारा इस कोरोना काल में सकारात्मक पहल की गई है। विभाग द्वारा ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता का निधन कोरोना के कारण हो गया है अथवा जिनके माता–पिता इस बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, उनके भरण–पोषण की जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया गया है। ऐसे बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की जा रही है। ग्वालियर जिले में इसके तहत फिट फेसिलिटी केन्द्र की शुरुआत की जा रही है। जिले में संचालित शासकीय विद्यालय और छात्रावासों को ऐसे बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए फिट फेसिलिटी केन्द्र घोषित कर बच्चों की उचित देखभाल तथा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ता आदि को जोड़कर बच्चों को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।

उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत बच्चों को शासकीय एवं निजी प्रायोजन सहायता का मुख्य उद्देश्य उनके जैविक परिवार से अलग होने से रोकना है। साथ ही बाल देखरेख संस्था में रहने वाले बच्चे, मुक्त कराये गये बच्चों को उनके जैविक परिवार में भेजकर पुनर्वास स्थित करना एवं उनका समग्र विकास करना तथा सामाजिक रूप से सक्षम परिवारों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का बाल देखरेख संस्था में रहने वाले बच्चों के विकास में सहयोग के लिये जोड़ना है।

अद्भुत दृश्य है ये, सभी मानवता की सेवा में लगे हैं : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यदि सकारात्मक ऊर्जा के साथ कोरोना का सामना किया जाए, तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अद्भुत दृश्य है ये, सभी मानवता की सेवा में लगे हैं। कोरोना के खिलाफ युद्ध को आपने नई दिशा दी है। आपके इस भागीरथी प्रयास को मैं प्रणाम करता हूँ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर में हाल ही में राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा बनाए गए 1200 बिस्तरीय माँ अहिल्या कोविड केअर सेन्टर के संचालक, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, मरीजों आदि से बातचीत की। उन्होंने कोविड सेंटर का वर्चुअल अवलोकन भी किया। इस अवसर पर इंदौर से मंत्री श्री तुलसी सिलावट, केंद्र के संचालक डॉ निशांत खरे आदि शामिल हुए।

मध्यप्रदेश का प्रथम तथा देश का द्वितीय सेंटर

चिकित्सा संबंधी सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह मध्यप्रदेश का पहला तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है। इसे रिकॉर्ड 6 दिन में तैयार किया गया, जिसमें दो चरणों में 600–600 बेड तैयार किए गए हैं। 250 एकड़ में फैले हुए इस केंद्र में 35 एकड़ में शेड बनाया गया है। परिसर में 12 हजार पेड़ तथा 3,000 टॉयलेट है। यहां शत–प्रतिशत वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ऑक्सीजन

प्लांट लगाए जा रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए योग, प्राणायाम, स्टीम लेने, नाश्ते, भोजन, कोविड जाँच, उपचार आदि व्यवस्थाएँ हैं। यहां 65 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए गए हैं। इस केंद्र का संचालन इंदौर के चार बड़े चिकित्सालय मेदांता, अपोलो, चोइथराम एवं बॉम्बे हॉस्पिटल की टीम द्वारा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान से चर्चा के दौरान केंद्र में भर्ती राजमोहल्ला इंदौर के श्री देवेंद्र भावसार ने बताया कि वे कोरोना पॉजिटिव आने के बाद निराशा की स्थिति में अपने घर में पड़े थे। फिर जब उन्हें इस सेंटर के बारे में पता चला और वे यहाँ आए तो उनके जीवन में आशा एवं विश्वास जागा। अब लग ही नहीं रहा कि वे बीमार हैं।

केंद्र में भर्ती सुश्री अंजलि तथा वंशिका ने बताया कि वे 5 दिन पहले इस केंद्र में भर्ती हुई हैं। शुरू में तो उन्हें डर लग रहा था, परंतु अब वे बहुत खुश हैं। इस केंद्र में कोविड–19 इलाज के साथ ही मोटिवेशन भी दिया जाता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान से बातचीत के दौरान डॉक्टर अंजली एवं नर्स लक्ष्मी ने बताया कि अस्पताल के और यहाँ के वातावरण में बहुत अंतर है। अस्पताल में मरीज को डर लगता है, वहीं यहाँ पर मरीज घर जैसा महसूस कर रहे हैं। पूरा एक परिवार लगता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को केंद्र की संचालक डॉ. शिप्रा श्रीवास्तव ने बताया कि इतने कम समय में जिला प्रशासन इंदौर द्वारा इतने विशाल एवं सर्व सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर का निर्माण अकल्पनीय है। कोरोना महामारी जैसी नेशनल इमरजेंसी के दौरान यह मानवता की बहुत बड़ी सेवा है।

मुख्यमंत्री चौहान ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के ट्रस्टियों से भी बातचीत की तथा उनका आभार प्रकट किया।

(पृष्ठ 1 का शेष)

75 लाख किसानों के खाते में जमा.....

सरकार कठिन परिस्थितियों में भी किसानों के साथ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि सारा देश और दुनिया कोविड के संकट से जूझ रही है। सरकार का राजस्व भी आधा रह गया है। कोविड रोगियों के उपचार पर भारी धनराशि व्यय हो रही है। मरीजों का उपचार सरकार की प्राथमिकता और धर्म है। सरकार उसका पालन कर रही है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार विकट परिस्थितियों के बावजूद किसानों के साथ लगातार खड़ी है। उनके कल्याण के कार्य कर रही है। आगे भी यह कार्य होगे, जिनका उल्लेख समय पर किया जाएगा।

गरीब का निःशुल्क उपचार होगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब व्यक्ति का निःशुल्क उपचार होगा। प्रदेश के समस्त सरकारी और अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की प्रचलित व्यवस्था के साथ ही आयुष्मान कार्ड के पैकेज में 40 प्रतिशत राशि वृद्धि कर गरीब के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था को मज़बूत बनाया गया है। आयुष्मान कार्डधारी व्यक्ति के पूरे परिवार को निःशुल्क उपचार की पात्रता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्डधारी है।

किल कोरोना अभियान में ग्रामीण करे सहयोग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा आदि का वितरण किया जा रहा है। संक्रमण की रोकथाम के लिए उसकी चेन को तोड़ना जरुरी है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति की जल्द से जल्द पहचान जरुरी है। इसके लिए किल कोरोना अभियान में घर–घर सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है। अभियान की सफलता के लिए ग्रामीण जन का सहयोग जरुरी है।

सर्वेक्षण टीम के सहयोग हेतु ग्रामीणों का बने दल

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्राम स्तरीय शासकीय अमले की टीम गाँव के प्रत्येक घर में जाकर संक्रमितों को चिन्हित करने का कार्य कर रही है। उसके साथ ग्राम के सेवाभावी व्यक्तियों का दल भी जाए। इससे सर्वेक्षण कार्य प्रभावी बनेगा। कोरोना से लड़ाई में सफलता तभी मिलेगी, जब गाँव के लोग लड़ाई में भाग लें। सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सर्दी, जुकाम, खाँसी और बुखार के लक्षण दिखते ही जाँच करायें और दवाएँ शुरु कर दे। मुख्यमंत्री ने स्वयं का उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे ही तेज बुखार आया तुरंत जाँच कराकर दवाईयाँ लेने से वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गए थे।

कोविड केयर सेंटर पर ले जायें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि घर में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं होने पर रोगी को कोविड केयर सेंटर में भिजवा दें। वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएँ की गई हैं। ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सेंटर पर चिकित्सकों द्वारा फोन पर परामर्श, योग आदि की व्यवस्थाएँ भी की गई हैं।

घर में रह कर कोरोना से लड़ने में करे सहयोग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना से सरकार अकेले नहीं लड़ सकती, क्योंकि कोरोना संक्रामक रोग है, एक से दूसरे में फैलता है। इसलिए उपचार की व्यवस्थाओं को बढ़ाकर लड़ाई जीती नहीं जा सकती, जरुरी है कि संक्रमण की चेन तोड़ें। घर में रह कर गाँव और घर को कोरोना से सुरक्षित करें।

कोरोना मुक्त गाँव बनायें, प्रवेश पर लगायें रोक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन गाँवों में कोरोना का संक्रमण नहीं फैला है, उन ग्रामों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को रोक दें। गाँव से कोई भी बाहर नहीं जाए। आवश्यक होने पर एक दो व्यक्ति जाकर सभी के लिए जरुरी सामान ले आयें। यदि बाहर से किसी व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए, तो उसकी भली–भाँति बुखार आदि की जाँच करें। आवश्यकता अनुसार क्वारेंटाइन करें। उन्होंने कहा कि गाँव सुरक्षित तो सब सुरक्षित होंगे।

मई माह में नहीं करे शादी–ब्याह

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विवाह जीवन साथी के लिए होते हैं। साथी के जीवन को संकट में डालना उचित नहीं है। इसलिए मई माह में सारे पारवारिक, सामुदायिक और सामाजिक आयोजन नहीं करें। कही भी भीड़ नहीं लगे।

राशन वितरण व्यवस्था में सहयोग करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 3 माह का और केन्द्र सरकार की ओर से दो माह का राशन निःशुल्क मिलेगा। प्रति व्यक्ति के मान से परिवार को 5 माह का राशन मिलेगा। वितरण के समय भीड़ नहीं लगे। इसकी व्यवस्था में ग्रामीण जन सहयोग करें।

जन–सहयोग से मध्यप्रदेश संक्रमण नियंत्रण में अग्रणी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए जनता द्वारा कर्फ्यू की व्यवस्था के अच्छे परिणाम दिखने लगे हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 25 प्रतिशत से घट कर 17–18 प्रतिशत हो गई है।

निरंतर उपचार व्यवस्थाएँ हो रहीं बेहतर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में उपचार व्यवस्थाएँ निरंतर बेहतर हो रही हैं। हवाई जहाज और रेल की विशेष व्यवस्थाओं के द्वारा ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त हो गई है। दवाईयों की भी कमी नहीं होने दी जाएगी।

अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़कर 61 हजार हो गई है। इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है।

अस्पतालों में नहीं बनेंगे वैक्सीनेशन केन्द्र

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वैक्सीनेशन केन्द्र अस्पतालों में नहीं अन्य स्थानों, स्कूल आदि में होगा। प्रतिमाह 9 लाख वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो गई है। सरकार द्वारा 5 करोड़ से अधिक वैक्सीन का आर्डर दिया गया है। जैसे–जैसे उपलब्धता बढ़ेगी कार्य में गति आएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन जरुर करायें। वैज्ञानिको ने हर कसौटी पर परख कर वैक्सीन लगवाने के लिए कहा है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

कोई भी गरीब बिना राशन के नहीं ....

राशि भुगतान कर लेने वालों को भी मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन गरीब परिवारों द्वारा अप्रैल एवं मई माह का खाद्यान्न राशि का भुगतान कर प्राप्त किया है, उन्हें भी आगामी माह में निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाये। उनको बताया गया कि ऐसे हितग्राहियों को जुलाई और अगस्त माह में निःशुल्क अनाज वितरण किया जायेगा।

शेष रहे परिवारों को 5 माह का खाद्यान्न एकमुश्त मिलेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान को बैठक में बताया गया कि 15 मई के पश्चात खाद्यान्न प्राप्त करने से शेष रहे परिवारों को 5 माह का खाद्यान्न एकमुश्त वितरित होगा। प्रदेश के कुल एक करोड़ 11 लाख 29 हजार 273 परिवारों में से 91 लाख 25 हजार 513 ने अप्रैल माह का राशन प्राप्त कर लिया है। मई माह का राशन प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 56 लाख 38 हजार 678 और जून माह का राशन प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 20 लाख 45 हजार 719 है।

कृषि आदानों का समय पूर्व भंडारण सुनिश्चित करें : मंत्री श्री पटेल

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने विभागीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को खरीफ 2021 के लिए आवश्यक कृषि आदानों का समय पूर्व भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रदेश के समस्त कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया।

श्री पटेल ने वी.सी. से खरीफ 2021 की तैयारी की विभागीय समीक्षा की। उन्होंने खरीफ के लिए आवश्यक कृषि आदानों बीज, उर्वरक, दवाइयों की आवश्यकतानुसार समय से पूर्व भंडारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि उर्वरक, बीज, दवा की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निर्माण स्थल पर लॉट वार नमूना लेकर प्रमाणिक होने पर ही भंडारण कराया जाएं। प्रदेश में बीज की आपूर्ति बीज उत्पादक संस्थाओं से जिलों में पूर्ति कराई जाएं।

श्री पटेल ने प्रदेश में बीज की मांग एवं आपूर्ति समय पर सुनिश्चित करने के लिए समग्र नीति बनाने को कहा है। उन्होंने बीज की दरें तत्काल तय कर जारी करने के निर्देश दिए हैं। श्री पटेल ने बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा उत्पादित बीज की मात्रा का शतप्रतिशत सत्यापन कराये जाने को भी कहा है। मंत्री श्री पटेल द्वारा समीक्षा बैठक में बी टी कॉटन के बीज की व्यवस्था करने के निर्देश संयुक्त संचालक, इंदौर को दिए गए। सोयाबीन फसल में बढ़ते जोखिम के दृष्टिगत जिलों की कृषि जलवायु अनुसार धान, अरहर, मूंग,उडद, मक्का फसल को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। श्री पटेल ने चना, मसूर, सरसो की समय पर उपार्जन की व्यवस्था विभाग द्वारा किये जाने से किसानों को अच्छा मूल्य मिलने पर प्रशंसा की। समीक्षा बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संचालक कृषि के साथ विभाग के समस्त अपर संचालक, संयुक्त संचालक एवं जिलों के उपसंचालक उपस्थित रहे।

कोरोना मरीजों के परिजनों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा मरीजों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य आहार सेवा योजना शुरू

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने भोपाल में योजना का किया शुभारंभ

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंगलवार को भोपाल के कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क स्वस्थ आहार सेवा योजना शुरू की। इस योजना के शुरू हो जाने से अब कोरोना मरीज के परिजनों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मरीज जिस अस्पताल में भर्ती है, वहीं समय पर उसे पौष्टिक आहार निःशुल्क मिल जायेगा। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना भोपाल के 110 अस्पताल में शुरू की गई है। इसकी सफलता पर प्रदेश के अन्य शहरों में भी इस योजना को शुरू किया जायेगा। योजना के शुभारंभ के अवसर पर भोपाल कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया भी उपस्थित थे।

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि जिला आपदा प्रबंध समिति और कोरोना कर्फ्यू की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात सामने आयी थी कि कोरोना कर्फ्यू के कारण अस्पतालों में मरीजों को भोजन पहुँचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कोरोना मरीज के लिए भोजन लेकर उसके परिजन अस्पताल आते हैं, तो उनके संक्रमित होने की संभावना लगातार बनी रहती है। इसलिए अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था सरकार ने स्वयंसेवी संगठनों और जन–सहयोग से शुरू की है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अब कोरोना मरीज के परिजनों को परेशान नहीं होना पड़ेगा और उनके संक्रमित होने का डर भी नहीं रहेगा। साथ ही मरीज को भी अस्पताल में समय पर पौष्टिक आहार मिल जायेगा। वैसे भी इस दौरान मरीज के जल्दी स्वस्थ होने के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत होती है।

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि निःशुल्क स्वस्थ आहार सेवा योजना के लिए एक हेल्प लाइन नंबर भी जल्दी शुरू किया जा रहा। इस नंबर पर मरीज के परिजन जिस अस्पताल में मरीज भर्ती है, वहाँ भोजन पहुँचाने के लिए बता सकेंगे।

गरीब का निःशुल्क उपचार शासन की जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री

राष्ट्रीय औसत से कम हुई प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट • मुख्यमंत्री ने की कोरोना कोर ग्रुप की विडियों कॉन्फ्रेंस

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि गरीब के उपचार की व्यवस्था शासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था के लिए चिकित्सालय चिन्हित किए गए है। इसके साथ ही गरीब के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्थाओं को अधिक विस्तारित करने के संबंध में प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि सी.टी. स्कैन की निर्धारित दरों को कम करने के तरीकों पर भी विचार किया जाए। दर ऐसी हो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा भी वहन की जा सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज कोरोना कोर ग्रुप की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मुख्यमंत्री निवास से संबोधित कर रहे थें। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 4 मई को राष्ट्रीय औसत से कम हो गई है। राष्ट्रीय औसत 21.6 प्रतिशत की तुलना में प्रदेश की औसत 20.7 प्रतिशत हो गई है।

निजी अस्पतालों में कोविड रोगियों का निर्धारित दर पर हो उपचार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब व्यक्तियों के उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड के साथ ही अन्य निःशुल्क उपचार की वैकल्पिक व्यवस्थाएँ भी की जाएँ। उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों का निजी चिकित्सालयों में उपचार शासन द्वारा निर्धारित शुल्क पर हो। इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि किसी भी चिकित्सालय को मनमानी दरों पर उपचार की छूट नहीं दी जाएगी। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एम्बुलेंस की दरें प्रति किलो मीटर के आधार पर निर्धारित करने के निर्देश दिए। इसी तरह सी.टी. स्कैन करवाने के परामर्श के लिए भी निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार व्यवस्थाएँ कराने की जरूरत बताई।

प्रभारी मंत्री ग्रामीण अंचल के कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था देखें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण अंचल के क्वारेंटाइन सेंटर और कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण करें और वहाँ की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाए। उन्होंने कहा कि क्वारेंटाइन और कोविड केयर सेंटरों की व्यवस्थाओं के संबंध में जन–जागरण भी किया जाए, ताकि संक्रमित व्यक्ति को वहाँ पर रख कर संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी आकस्मिक रूप से ग्रामीण अंचल के कोविड केयर और क्वारेंटाइन सेंटर का निरीक्षण करेंगे।

बीना रिफायनरी में 200 ऑक्सीजन बिस्तर का अस्पताल शीघ्र होगा प्रारम्भ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बीना रिफायनरी में बनने वाले अस्पताल के निर्माण कार्य की समीक्षा की। बताया गया कि मई माह के मध्य तक 200 ऑक्सीजन बिस्तर का अस्पताल प्रारम्भ हो जाएगा। साथ ही उन्होंने मोहासा–बाबई में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लान्ट की गति को भी तीव्र करने के निर्देश दिए। साथ ही इंदौर में ई. एस.आई. के चिकित्सालय में शीघ्र ही कोविड केयर सेंटर शुरु हो जाएगा।

ऑक्सीजन उपलब्धता की स्थिति हुई बेहतर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। बताया गया कि ऑक्सीजन उपलब्धता की स्थिति बेहतर हुई है। 2 मई को ऑक्सीजन की 516 मीट्रिक टन आवश्यकता की तुलना में 683 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। प्रदेश को आवंटित ऑक्सीजन मात्रा की तुलना में 90 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार ठीक ढंग से हो रही है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आगामी 2 दिन की ऑक्सीजन आवश्यकता से अधिक का भंडारण हो गया है। प्रदेश में ऑक्सीजन भंडारण क्षमता पूर्णता की ओर तेजी से बढ़ रही है। विगत चार दिनों में 4 नये ऑक्सीजन टैंकर भी प्राप्त हुए है। आगामी 2–3 दिनों में सिंगापुर से अयातित दो टैंकर भी प्राप्त हो जाएगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर संचालन टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी और कहा कि मॉनीटरिंग की गहनता बनी रहे।

अस्पताल से डिस्चार्ज होने वालों की बढ़ी संख्या

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में आज 12 हजार 236 नये पॉजिटिव केस मिले हैं। चिकित्सालयों से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या में करीब 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिनांक 2 मई को डिस्चार्ज संख्या 1505 की तुलना में 3 मई को 1781 डिस्चार्ज हुए है।

नवाचार : भोपाल में 'ड्राइव इन वैक्सीनेशन' शुरू

भोपाल। भोपाल में बने मध्यप्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा में राज्य सरकार के प्रयासों से ''ड्राइव इन वैक्सीनेशन'' शुरू हुआ है। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से राज्य पयर्टन निगम की श्यामला हिल्स स्थित होटल लेक व्यू के परिसर में इसका संचालन किया जा रहा है।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचकर व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन करवाने आए व्यक्तियों से उनका हालचाल जाना और अन्य लोगों को भी इस नये प्रयोग के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। श्री सारंग ने कहा कि विशेषकर वृद्धजनों और महिलाओं के लिए यह टीकाकरण कार्यक्रम एक सुरक्षित और अनूठा प्रयोग है। इस तरह के नये प्रयोग मध्यप्रदेश के अन्य स्थानों में भी किए जायेंगे। इस अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री एस विश्वनाथन और कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया भी उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि भोपालवासियों को सुरक्षित और सुलभ वैक्सीनेशन की सुविधा के लिये यह नया प्रयोग शुरू किया गया है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन के अंतर्गत प्रतिदिन शाम 5 बजे से 8 बजे तक 45 वर्ष से अधिक आयु के (प्री –रजिस्टर्ड) नागरिकों को टीका लगाया जायेगा। वैक्सीनेशन के लिए नागरिक अपनी सुविधानुसार डेट और टाइम स्लॉट लेने के लिये <https://cowin.gov.in/> पोर्टल और आरोग्य सेतु एप (Arogya Setu App) के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। एप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होने पर डेट एवं टाइम स्लॉट का स्क्रीन शॉट या प्रिंट आउट के साथ ही वह फ़ोटो पहचान–पत्र लाना होगा, जिससे रजिस्ट्रेशन किया गया है। इससे नागरिक निर्धारित तिथि और समय पर पहुँचकर वैक्सीनेशन करा सकेंगे। ड्राइव इन वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों और कोविड–19 प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री एस. विश्वनाथन ने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा वैक्सीनेशन कराने वाले लोगो को इसी परिसर में ही रहना पड़ेगा, हालांकि इस दौरान परिसर में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव और रोकधाम के संबंध में बड़ी स्क्रीन पर रोचक जानकारी भी दी जाएगी। वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान स्वास्थ्य विभाग के स्टॉफ सहित पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टॉफ भी मौजूद रहेगा, ताकि रोज़ाना समय पर वैक्सीनेशन ड्राइव की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही व्यक्तियों की सुविधा के लिए चिकित्सीय वैन भी उपलब्ध रहेंगी।

पिक एण्ड ड्रॉप की सुविधा भी

श्री विश्वनाथन ने बताया कि सुरक्षित वैक्सीनेशन के लिए लोगों के लिये पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी शुरू की गई है। इच्छुक व्यक्ति पर्यटन निगम के परिवहन शाखा के नंबर 90397 61097 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्हें 10 किलोमीटर तक 400 रुपए, 20 किलोमीटर तक 600 रुपए और 35 किलोमीटर तक के लिए 900 रुपए का शुल्क देना होगा। ऐसे नागरिकों को निगम की परिवहन शाखा द्वारा उनके घर से पिक करके वैक्सीनेशन होने के बाद वापस घर तक ड्रॉप किया जाएगा।

दिवंगत सहकारिता कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

भोपाल। प्रदेश में दिवगंत सोसायटी कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को राज्य सरकार अनुकंपा नियुक्ति देगी। इस संदर्भ में सहकारिता विभाग द्वारा बुधवार देर शाम आदेश जारी कर दिए गए है।

विभाग के आयुक्त नरेश पाल द्वारा कलेक्टरों को जारी आदेश में कहा गया है कि यदि सहकारी साख समितियों के नियमित अथवा संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कोरोना संक्रमित होते हुए दिवंगत होते है तो उनके परिवारों में पात्र आश्रितों को अनुकंपा प्रदान की जाए। आदेश में यह स्पष्ट भी किया गया है कि यदि संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का निधन होता है तो उसे विशेष परिस्थितियों में इन्हीं पदो पर अनुकंपा दी जाएगी। उसे नियमितीकरण की पात्रता नहीं रखे रहेगी। इसके लिए संचालक मंडल और प्रशासक अधिकृत होगा। कोरोना योद्धा के संबंध में भी आदेश जारी किए गए है। कलेक्टरों से कहा गया है कि वे इस विषय में विचार करें। आदेश में यह भी बताया गया है कि अभी तक 77 कर्मचारियों की मौत हुई है। जिनकी जानकारी प्रेषित करने के निर्देश भी दिए गए है ताकि इनके पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जा सके।

सहकारिता मंत्री से चर्चा के बाद आज से होने वाली काम बंद हड़ताल स्थगित

यहां बता दे कि समस्याओं को लेकर सहकारिता समिति कर्मचारियों के महासंघ द्वारा गुरूवार, छह मई से काम बंद हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। इसके बाद विभाग हरकत में आया और इन्हे सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुवर बीएस चौहान का आरोप था कि प्रदेश में काम करते हुए 60 से अधिक साथी कर्मचारियों की मौत हो गई है। इसके बाद भी सरकार ने ना तो कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है ना ही आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसके अलावा लगभग 200 कर्मचारी विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण से जूझ रहे है। बुधवार की दोपहर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से विस्तार से चर्चा करने के बाद कर्मचारियों ने

अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है।

कोरोना से दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को देंगे आर्थिक सहायता : भदोरिया

इस संदर्भ में सहकारिता मंत्री अरविंद भदोरिया ने दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि जो सोसाइटी कर्मचारी कोरोना संक्रमण के बाद दिवंगत हुए है इनके परिवारों में पात्र आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद आदेश जारी हुए है। भदोरिया ने बताया है कि हम पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता भी देने जा रहे है। इसके लिए जानकारी मांगी गई है और राशि का निर्धारण किया जा रहा है। मंत्री श्री भदोरिया ने बताया है कि अपेक्स बैक के कर्मचारी नही है। उन्होने कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने के संबंध में भी केन्द्र सरकार की गाइडलाइन का हवाला दिया। मंत्री ने बताया कि केन्द्र शासन की गाइड लाइन में स्पष्ट है कि जो कर्मचारी अस्पतालों या अन्य जगहों पर कोरोना ड्यूटी करते समय संक्रमित होता है या उसके साथ कोई अनहोनी घटित होती है तो गाइड लाइन में ऐसे कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने का प्रावधान है।

पीपीपी पार्टनरशिप के माध्यम से एक दिन में 30 बालिकाओं को मिला रोजगार

भोपाल। आयुक्त रोजगार श्रीमती षणमुखा प्रिया मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को पीपीपी पार्टनरशिप के माध्यम से लगातार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में एक दिन मे प्रदेश के विभिन्न जिलों से 30 युवतियों ने बुधनी स्थित कारखाने में ज्वाइनिंग दी है। इसमें भोपाल से 15, विदिशा ,बालाघाट, छिंदवाड़ा एवं बैरसिया से 1–1 ,सीहोर 3, होशंगाबाद 6 तथा इटारसी से 2 युवतियाँ शामिल है। इसमें 10 युवतियाँ विभिन्न आईटीआई से हैं । इनका चयन इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा ड्राफ्ट्समैन के रूप में किया गया है।

श्रीमती मिश्रा ने बताया कि रोजगार कार्यालय की पीपीपी पार्टनर यशस्वी अकादमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट द्वारा इस लॉकडाउन पीरियड में वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं के इंटरव्यू कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार के लिए इच्छुक युवा अपना पंजीयन <www//mprojgar.gov.in> पर करा सकते हैं।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी

डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।